PRESS RELEASE

Virtual Inauguration of Legal Services Clinics under NALSA Veer Parivar Sahayta Yojna 2025 in Jharkhand

Ranchi, 13 September 2025

The Virtual Inauguration of Legal Services Clinics under the NALSA Veer Parivar Sahayata Yojna 2025 was held today across all districts of Jharkhand, dedicated to Defence Personnel, Ex-Servicemen, and their dependent family members. The programme was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, Chief Justice, High Court of Jharkhand cum Patron-in-Chief, JHALSA, at Kerketta Auditorium, Army Cantonment, Dipatoli, Ranchi, in the benign presence of Hon'ble Mr. Justice Sujit Narayan Prasad, Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA, along with Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar Dwivedi and Hon'ble Mr. Justice Sanjay Prasad, Judges, High Court of Jharkhandand Major General Sajjan Singh Maan, GOC, 23 Infantry Division, Brigadier Raj Kumar, Sena Medal, Deputy GOC, 23 Infantry Division.

The august occasion was also graced by senior Army officers, judicial officers,DIG cum Senior Superintendent of Police, Deputy Commissioner, Ranchi, Chairpersons, and Secretaries of DLSAs, who joined virtually from all districts of Jharkhand.On this occasion, a 90-Day Campaign under Veer Parivar Sahayata Yojna was also launched by the Chief Justice and other dignitaries with the objective of creating wide awareness and identifying maximum beneficiaries so that immediate relief may be provided to them.

Delivering the **Welcome Address**, **Ms. Kumari Ranjana Asthana, Member Secretary, JHALSA**, highlighted the achievements of JHALSA under the leadership of its Patron-in-Chief and Executive Chairman, noting that JHALSA has been making tremendous strides in expanding its outreach to the remotest corners of Jharkhand. She also said that the purpose of launching the campaign of veer Parivar Sahayata Yojna is to provide all possible legal assistance to defence personnels, Ex Servicemen and their dependent family members.

Major General Sajjan Singh Maan, GOC, 23 Infantry Division, in his Special Address, congratulated NALSA and JHALSA for conceptualizing and implementing the Veer Parivar Sahayta Yojna, terming it a landmark initiative for the welfare of defence personnel and their families.

In his remarks, **Hon'ble Mr. Justice Sujit Narayan Prasad**, Executive Chairman, JHALSA, said that the scheme was launched on the advice of the Hon'ble Chief Justice with the purpose of ensuring that immediate relief reaches beneficiaries in need of legal assistance. He emphasized that the object of the scheme is not only to provide legal aid to serving Army personnel and their dependents but also to make them aware of their legal and constitutional rights under Article 39A of the Constitution of India.

Addressing the gathering, the **Hon'ble Chief Justice** stated that *"Legal Services Clinics for bravehearts, veterans, and their families are not mere ceremonial events but a solemn pledge. This is the judiciary's humble tribute to those who have dedicated their lives to safeguarding the nation. The Judiciary of Jharkhand stands firmly with our soldiers."*

Alongside this event, the **National Lok Adalat** was successfully organized today across the state. **Around 288 Benches were constituted in National Lok Adalat**, wherein **1901846 Pre-litigation** and **160032 pending cases** were disposed of, resulting in settlement amounts worth **Rs 9,24,93,44,880.**

Issued by:
Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), Ranchi

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा झारखंड में नालसा वीर परिवार सहायता योजना **2025** के अंतर्गत पूरे राज्य में विधिक सेवा क्लिनिकों का वर्चुअल शुभारंभ

रांची, 13 सितम्बर 2025:

झारखंड राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के लिए नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के अंतर्गत विधिक सेवा क्लिनिकों का वर्चुअल शुभारंभ आज किया गया।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय सह संरक्षक, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) द्वारा आर्मी कैंट, दीपाटोली, रांची स्थित केरकेट्टा सभागार में किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, झालसा, तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय प्रसाद, झारखण्ड उच्च न्यायालय, आर्मी अफसर मेजर जनरल सज्जन सिंह मान, GOC, 23, Infantry, ब्रिगेडियर राज कुमार, Sena Medal, Deputy GOC, 23 Infantry, कुमारी रंजना अस्थाना, सदस्य सचिव झालसा अन्य वरिस्ठ सैन्य अधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी गण, पुलिस उपमहानिरीक्षक सह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त की भी गरिमामयी उपस्थिति रही |

इस अवसर पर सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं सचिव वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम के दौरान 90 दिवसीय वीर परिवार सहायता अभियान का भी शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें त्वरित राहत प्रदान करना है।

स्वागत भाषण में सुश्री रंजना अस्थाना, सदस्य सचिव, झाल्सा ने कहा कि माननीय संरक्षक-इन-चीफ एवं कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में झालसा निरंतर नई उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहा है और झारखंड के दूरदराज़ क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बना रहा है। माननीय सदस्य सचिव ने यह भी कहा कि इस वीर परिवार योजना के अंतर्गत सेना के जवान एवं अवकाश प्राप्त और उनके आश्रित परिवारों को विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा |

मेजर जनरल सज्जन सिंह मान**,** जीओसी**, 23** इन्फैंट्री डिवीजन ने अपने विशेष उद्बोधन में नालसा एवं झालसा को इस ऐतिहासिक योजना के लिए बधाई दी और इसे सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी पहल बताया।

अपने संबोधन में माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष, झाल्सा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल विधिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सैनिकों और उनके आश्रितों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद **39(**क**)** के अंतर्गत प्रदत्त विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि *"सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के लिए विधिक सेवा क्लिनिक केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गंभीर संकल्प है। यह न्यायपालिका की ओर से उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। झारखंड की न्यायपालिका सदा अपने सैनिकों के साथ खड़ी है।"*

इसी क्रम में, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भी सफल आयोजन पूरे राज्य में किया गया। **इस** राष्ट्रीय लोक अदालत **में कुल 288** पीठों का गठन किया गया, जिनमें कुल **19,01,846** वादपूर्व एवं **1,60,032** लंबित मामलों का निष्पादन हुआ तथा **₹9,24,93,44,880** की राशि का समझौता संपन्न हुआ।

प्रेषक**:**
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झाल्सा), राँची